भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5407
25.03.2026 को उत्तर देने के लिए

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

5407. प्रो. सौगत रायः

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) का माह और क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) जनवरी, 2026 के आईआईपी का विनिर्माण, खनन, विद्युत और उपभोक्ता के क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में अंतर का ब्यौरा क्या है;

(घ) औद्योगिक उत्पादन में सुधार सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों को दूर करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह)

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) का माहवार और क्षेत्रवार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(ख) विनिर्माण, खनन, विद्युत और उपभोक्ता क्षेत्रों में जनवरी 2026 के आईआईपी का विवरण नीचे दिया गया है:

क्षेत्र/उपयोग-आधारित श्रेणी	जनवरी-2026	
	सूचकांक	वृद्धि (%)
खनन	157.2	4.3
विनिर्माण	167.2	4.8
विद्युत	212.1	5.1
उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएँ	138.2	6.3
उपभोक्ता ग़ैर-टिकाऊ वस्तुएँ	160.7	-2.7

(ग) वास्तविक रूप में जीडीपी किसी अर्थव्यवस्था द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को दर्शाती है, जिसे आधार वर्ष की कीमतों में व्यक्त किया जाता है, इसे "स्थिर मूल्य" भी कहा जाता है। जबकि, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) देश में औद्योगिक उत्पादन वृद्धि की गति को दर्शाने वाला एक प्रमुख अल्पकालिक संकेतक है। विनिर्माण क्षेत्र के सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) के त्रैमासिक अनुमान के लिए आईआईपी एक महत्वपूर्ण इनपुट के रूप में कार्य करता है।

(घ) सरकार ने देश में निवेश बढ़ाने और औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार उचित नीतिगत हस्तक्षेपों द्वारा उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से देश के समग्र औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करती है। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में चालू योजनाओं के अतिरिक्त, सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में नए उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देने और सुगम बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, पीएम गतिशक्ति, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी), राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई), व्यापार करने में सहजता (ईओडीबी) को बढ़ावा देना और अनुपालन बोझ को कम करना, राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस), भारतीय औद्योगिक लैंड बैंक(आईआईएलबी), परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी), प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति का उदारीकरण, भारतीय जूता और चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएफएलडीपी) योजना, आदि। आर्थिक विकास को सुदृढ़ करने और वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए, सरकार ने लगातार अपनी वैश्विक व्यापार साझेदारियों का विस्तार किया है; उदाहरण के लिए, भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते में 15 वर्षों में 20 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता शामिल है, जबकि भारत-ईएफटीए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते में 15 वर्षों में 100 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता है, जिससे देश में आर्थिक विकास को समर्थन मिल रहा है।

(ङ) भारत विविध और टिकाऊ आपूर्ति श्रृंखलाओं का समर्थन करने और विकास, आर्थिक स्थिरता और समृद्धि को आगे बढ़ाने के लक्ष्य के साथ साझेदार देशों के बीच आर्थिक जुड़ाव और सहयोग को मजबूत करने के लिए क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। इसके अतिरिक्त, वाणिज्य विभाग ने एक व्यापक और समन्वित दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालयों/विभागों और उद्योग निकायों के प्रतिनिधियों से मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती संबंधी अध्ययन समूह (समूह) की स्थापना की है। अब तक समूह की चार बैठकें हो चुकी हैं। अपनी बैठकों के दौरान, समूह ने अध्ययन के लिए विश्लेषणात्मक ढांचे को अंतिम रूप दिया, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की, जिनमें फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरण, रसायन और उर्वरक, महत्वपूर्ण खनिज और धातु, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर तथा ऑटोमोबाइल शामिल हैं, और डेटा सामंजस्य एवं संरचित उद्योग सहभागिता के लिए तंत्र प्रस्तावित किए। समूह ने आयात में वृद्धि या व्यवधान की निगरानी के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली स्थापित करने की भी सिफारिश की। सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए उनके रणनीतिक महत्व, वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में उनके गहन एकीकरण और बाहरी आपूर्ति व्यवधानों के प्रति उनकी उच्च संवेदनशीलता के कारण, फार्मास्युटिकल और मेडिकल डिवाइस क्षेत्रों को पहले विस्तृत मूल्यांकन के लिए चुना गया है।

*****

अनुबंध

माह	खनन	विनिर्माण	विद्युत	सामान्य
जनवरी-23	136.1	145.5	186.6	147.4
फरवरी-23	129.2	137.6	174	139.3
मार्च-23	154.2	147.5	188	151.7
अप्रेल-23	122.6	138.8	192.3	140.7
मई-23	128.1	143.1	201.6	145.6
जून-23	122.3	141.6	205.2	143.9
जुलाई-23	111.9	142.1	204	142.7
अगस्त-23	111.9	144.4	220.5	145.8
सितंबर-23	111.5	141.5	205.9	142.3
अक्तूबर-23	127.4	142.1	203.8	144.9
नवंबर-23	131.3	139.3	176.3	141.1
दिसंबर-23	139.5	151.6	181.6	152.3
जनवरी-24	144.3	150.8	197.1	153.6
फरवरी-24	139.7	144.4	187.2	147.1
मार्च-24	156.2	156.2	204.2	160
अप्रैल-24	130.9	144.6	212	148
मई-24	136.5	150.4	229.3	154.7
जून-24	134.9	146.6	222.8	151
जूलाई-24	116.1	148.8	220.2	149.8
अगस्त-24	107.1	146.1	212.3	145.8
सितंबर-24	111.7	147.2	206.9	146.9
अक्तूबर-24	128.5	148.4	207.8	150.3
नवंबर-24	133.8	147	184.1	148.1
दिसंबर-24	143.2	157.2	192.8	158
जनवरी-25	150.7	159.5	201.9	161.6
फरवरी-25	141.9	148.4	194	151.1
मार्च-25	158.1	162.4	219.5	166.3
अप्रैल-25	130.7	149.1	215.7	151.8
मई-25	136.4	155.2	218.5	157.6
जून-25	123.2	152	220.1	153.3
जूलाई-25	107.7	157.7	228.4	156.2
अगस्त-25	114.2	151.6	221.1	151.8
सितंबर-25	111.2	155.4	213.4	153.7
अक्तूबर-25	126.2	151.3	193.4	151.1
नवंबर-25	141.6	159.5	181.3	158.7
दिसंबर-25	153.1	170.4	204.9	170.7